Drishti IAS

करेंट अफेयर्स राजस्थान

मई (संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

राजस्थान **4**

- विधानसभा अध्यक्ष ने किया राष्ट्रीय सहकार मेले का उद्घाटन 4
- नरेडको और राजस्थान आवासन मंडल के बीच हुआ एमओयू 4
- राजकीय मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में खुलेंगी 9 पुलिस चौकियाँ 5
- सवाई मानसिंह चिकित्सालय में स्थापित होगी स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब 5
- राजस्थान में खेल एवं खिलाड़ियों के लिये महत्त्वपूर्ण स्वीकृतियाँ 5
- जोधपुर में खुलेगी राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ 6
- मसूदा, रावतभाटा तथा नावां में खोले जाएंगे नर्सिंग महाविद्यालय 6
- राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2023 एवं ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल के समापन अवसर पर विभिन्न श्रेणियों में मिले पुरस्कार 7
- अजमेर के सिलोरी में होगी पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना 8
- प्रत्येक ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति का होगा गठन 8
- दिल्ली में निवास कर रहे प्रवासी राजस्थानी लोगों को मिली महत्त्वपूर्ण योजनाओं की सौगात 8
- प्रदेश के सभी ज़िलों के राजकीय विद्यालयों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन 9
- प्रधानमंत्री ने नाथद्वारा में विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण 9
- राजस्थान पुलिस अकादमी में बनेगी इंडोर शूटिंग रेंज 10
- बीकानेर में 1 नवीन संस्कृत विद्यालय और प्रदेश के 18 संस्कृत विद्यालय होंगे क्रमोन्नत 10
- जोधपुर शहर का 565वाँ स्थापना दिवस 10
- जयपुर व चित्तौड़गढ़ में खुलेंगे सैटेलाइट अस्पताल 12
- नदबई एवं लवाण के आयुर्वेद औषधालय को ब्लॉक आयुष चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी 13
- मुख्यमंत्री ने दी कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों को मिलने वाली पेंशन राशि में वृद्धि को मंज़ूरी 13
- 225 ब्लॉक मुख्यालयों पर खुलेंगे होम्योपैथिक औषधालय 13
- राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को मिला 'द गोल्डन ग्लोब टाइगर अवाड्र्स' 14
- प्रदेश के प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों के अंशकालीन पुजारियों के मानदेय में वृद्धि 14
- प्रत्येक संभाग में स्थापित होगा सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्टस स्कूल 15
- 16 राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय माध्यमिक में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी 15
- मरुधरा का मान-स्वच्छता सम्मान-समारोह-2023 15
- 'द साइबेरियन स्ट्रे' 16

नोट :

- भारत में राज्यों की राजनीति 17
- अब हर ज़िले में दो लवकुश वाटिकाएँ 18
- जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर शहर बनेंगे थ्री डी सिटी 18
- राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022-23 19
- आहूस (डेनमार्क) एवं राजस्थान सरकार के बीच हुआ एमओयू 20
- मुख्यमंत्री ने किया राज्य स्तरीय कला महोत्सव का शुभारंभ 21
- चिकित्सा शिक्षा विभाग और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू 22
- वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. विनोद सोमानी हंस के कहानी संग्रह का विमोचन 22
- मुख्यमंत्री ने किया 'जंगल सफारी'का उद्घाटन 23
- विदेशी धरा पर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को दो श्रेणियों में मिले 'द गोल्डन ग्लोब टाइगर अवाडर्स' 24
- कृषि संकाय में अध्ययनरत छात्राओं की प्रोत्साहन राशि में तीन गुणा बढ़ोतरी 24
- मुख्यमंत्री ने किया अत्याधुनिक बस टर्मिनल का उद्घाटन 25
- राज्य के 5 संभागों में खोले जाएंगे आर-केट केंद्र 26
- डूंगरपुर में राजकीय विधि महाविद्यालय का शिलान्यास 26
- प्रदेश के 23 लाख किसानों को मिलेंगे प्रमुख फसलों के बीज मिनिकिट 26
- पोषण सूचकांकों में सुधार के लिये खरीदे जाएंगे 16.97 करोड़ रुपए के उपकरण 27
- राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश बने ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह 27

The Vision

नोट :

राजस्थान

विधानसभा अध्यक्ष ने किया राष्ट्रीय सहकार मेले का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

28 अप्रैल, 2023 को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी ने जवाहर कला केंद्र, जयपुर में दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, 2023 का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस मेले में तमिलनाडु, उत्तराखंड, केरल, पंजाब की सहकारी संस्थाओं सहित अन्य सहकारी समितियाँ अपने उत्पाद लेकर आई हैं। इससे व्यापार में इज़ाफा होगा। प्रतिस्पर्धा के युग में लोगों का सहकारी उत्पादों पर विश्वास नि:संदेह ज्यादा रहता है। यह मेला 7 मई तक चलेगा।
- इस मेले में केरल से आई सहकारी समिति की ओर से हल्दी, मिर्ची, नारियल तेल, केरल चिप्स, मसाले, नमकीन सहित कई विशिष्ट उत्पाद बिक्री के लिये आकर्षण का केंद्र है।
- इस बार राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला में साबुत एवं पीसे हुए मसालों के साथ-साथ ठंडक देने के लिये शरबत एवं ठंडाई की विशेष उत्पाद उपलब्ध कराए गए हैं। मेले में नाथद्वारा की विशेष ठंडाई आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
- उदयपुर भंडार एवं राजसमंद भंडार द्वारा खस, पान, गुलाब आदि के शरबत की विस्तृत रेंज शहरवासियों के लिये लाई गई हैं।

नरेडको और राजस्थान आवासन मंडल के बीच हुआ एमओयू

चर्चा में क्यों ?

2 मई, 2023 को केंद्रीय एजेंसी नेशनल रियल एस्टेट डवेलपमेंट काउंसिल (NAREDCO) और राजस्थान आवासन मंडल के मध्य एक एमओयू साइन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस एमओयू के तहत आगामी 2 वर्षों में 'निपुण' (नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स) कार्यक्रम के अंतर्गत दोनों संस्थाएँ मिलकर राज्य के 20 हज़ार निर्माण श्रमिकों को ऑन साइट कौशल प्रशिक्षण देगी।
- नरेडको के वाइस प्रेसिडेंट अशोक पाटनी ने बताया कि इस प्रशिक्षण के लिये काउंसिल ने राजस्थान आवासन मंडल को नोडल एजेंसी बनाया है। मंडल के सहयोग से पहले चरण में मंडल के अधीन प्रदेश भर में चल रही 150 से अधिक परियोजनाओं से जुड़े हज़ारों श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके पश्चात् प्रदेश की अन्य संस्थाओं को जोड़ा जाएगा।
- प्रशिक्षण के बाद निर्माण श्रमिकों को 3 साल के लिये 2 लाख रुपए का नि:शुल्क दुर्घटना बीमा भी करवाया जाएगा।
- इस एमओयू के बाद आवासन मंडल देशभर में पहली ऐसी संस्था बन जाएगी जो सरकारी, गैर सरकारी, देहाड़ी पर आने वाले, बिल्डरों के निर्माण श्रमिकों को नरेडको के सहयोग से प्रोफेशनल तरीके से प्रशिक्षित कराएगी। यह प्रशिक्षण चल रहे काम के दौरान ऑन साइट ही दिया जाएगा, जिससे निर्माण कार्य भी बाधित नहीं होगा।
- प्रशिक्षण समाप्ति पर श्रमिकों को नरेडको द्वारा प्रमाणपत्र एवं 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इसमें मंडल पर कोई भी वित्तीय भार नहीं आएगा। इस प्रशिक्षण की सबसे बड़ी खास बात यह है कि प्रशिक्षण लेने के बाद श्रमिक अकुशल से कुशल की श्रेणी में आ सकेंगे, जिससे उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी होगी।
- प्रशिक्षण से श्रमिकों को होने वाले लाभ-
  - प्रशिक्षण में सफल उम्मीदवारों को सरकार द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

नोट :

- प्रशिक्षण के बाद निर्माण श्रमिकों के आत्मसम्मान में होगी बढ़ोतरी।
- अकुशल से कुशल श्रेणी में आने से मिलने वाला पारिश्रमिक भी बढ़ेगा।
- प्रशिक्षण के बाद मिले सर्टिफिकेट से अन्य कार्यों में भी प्राथमिकता मिलेगी।
- प्रशिक्षण समाप्ति पर श्रमिकों को नरेडको द्वारा प्रमाणपत्र एवं 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।
- प्रशिक्षण लेने वाले निर्माण श्रमिक निशुल्क दुर्घटना बीमा योजना से भी लाभान्वित होंगे।
- प्रशिक्षित श्रमिकों को नई स्किल सीखने के साथ नए उपकरणों और तकनीकों की भी जानकारी मिलेगी।
- व्यक्तिगत सुरक्षा की जानकारी से निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

राजकीय मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में खुलेंगी 9 पुलिस चौकियाँ

चर्चा में क्यों ?

3 मई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में राजकीय मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में 9 पुलिस चौकियों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- यह पुलिस चौकियाँ राजकीय जनाना अस्पताल मेडिकल कॉलेज भरतपुर, राजकीय हरिबक्श कांवटिया चिकित्सालय जयपुर, टी.बी. अस्पताल शास्त्रीनगर जयपुर, राजकीय डेंटल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सुभाष नगर जयपुर, आर.यू.एच.एस. मेडिकल कॉलेज जयपुर, एस.आर. गोयल सैटेलाईट अस्पताल सेठी कॉलोनी जयपुर, राजकीय आर.डी.बी.पी. जयपुरिया अस्पताल जयपुर, राजकीय मनोचिकित्सालय, ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर एवं राजकीय जे.के.लोन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय कोटा में स्थापित होंगी।
- इन चौकियों में प्रत्येक में 1 उप निरीक्षक तथा 6 कॉन्स्टेबल अर्थात् कुल 9 उपनिरीक्षक तथा 54 कॉन्स्टेबल के पदों का सृजन भी किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध चिकित्सालयों में पुलिस चौकियाँ खोलने की घोषणा की थी।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय में स्थापित होगी स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब

प्रमुख बिंदु

4 मई, 2023 को राजस्थान जयपुर के सवाई मानसिंह एसएमएस चिकित्सालय में स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब की स्थापना के लिये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 8 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- इस लैब से एसएमएस चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा तथा मरीजों को समयबद्ध रूप से बेहतर इलाज मिल सकेगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023.24 के बजट में लैब की स्थापना के संबंध में घोषणा की थी।
- स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है, जिसे तत्काल मेडिकल केयर देने की आवश्यकता रहती है क्योंकि इस स्थिति में मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन या न्यूट्रेंट्स प्राप्त नहीं होते हैं। जिससे मस्तिष्क की कोशिकाएं (ब्रेन सेल) मर जाती हैं।

राजस्थान में खेल एवं खिलाड़ियों के लिये महत्त्वपूर्ण स्वीकृतियाँ

चर्चा में क्यों ?

4 मई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में ऑलवेदर स्वीमिंग पूल, भरतपुर में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स तथा बारां के शाहबाद में स्टेडियम व खेल छात्रावास बनाने के लिये 22.68 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स भरतपुर का निर्माण कार्य 7 करोड़ रुपए की लागत राशि से आरएसआरडीसी द्वारा किया जाएगा। साथ ही, जोधपुर के स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में ऑलवेदर स्वीमिंग पूल का निर्माण कार्य 8.68 करोड़ रुपए की लागत राशि से होगा।
- वहीं शाहबाद के स्टेडियम तथा खेल छात्रावास का निर्माण कार्य 7 करोड़ रुपए की लागत राशि से आरएसआरडीसी द्वारा किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में खेल से संबंधित उक्त घोषणाएँ की गई थीं।

जोधपुर में खुलेगी राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ

चर्चा में क्यों ?

5 मई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में 'राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण'की स्थायी पीठ खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने यह निर्णय राज्य कार्मिकों की सुविधा के दृष्टिगत लिया है। इस पीठ का संचालन जोधपुर हाईकोर्ट के पुराने हेरिटेज भवन के कोर्ट नंबर-19 में किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने इस स्थायी पीठ में सदस्य के 2, सहायक रजिस्ट्रार का 1, सूचना सहायक के 2, वरिष्ठ सहायक के 2, कनिष्ठ सहायक के 3 एवं निजी सहायक ग्रेड-2 के 3 पदों सहित कुल 13 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। कार्यालय के लिये आवश्यक उपकरण एवं फर्नीचर हेतु 25 लाख रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री के इस निर्णय से राज्य कार्मिकों के सेवा से जुड़े प्रकरणों जैसे पेंशन, वेतन निर्धारण, पदोन्नति आदि का त्वरित निस्तारण हो सकेगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी।

मसूदा, रावतभाटा तथा नावां में खोले जाएंगे नर्सिंग महाविद्यालय

चर्चा में क्यों ?

5 मई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अजमेर के मसूदा, चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा तथा नागौर के नावां में नवीन राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय खोलेने की मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- इन नवीन महाविद्यालयों के संचालन के लिये 17.70 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान की भी मंजूरी दी गई है।
- इसके साथ ही, प्रत्येक महाविद्यालय के लिये 24 नवीन पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। इन पदों में, प्रत्येक महाविद्यालय में प्राचार्य, उप-प्राचार्य, प्रोफेसर का एक-एक पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पद, सहायक प्रोफेसर के 3 पद, ट्यूटर के 8 पद, एक्सीक्यूटिव असिस्टेंट के 7 पद, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष का एक पद शामिल हैं।
- प्रत्येक महाविद्यालय के लिये मल्टी टास्किंग स्टाफ के 10 पदों पर एजेंसी के माध्यम से तथा सिक्योरिटी गार्ड के 10 पदों पर राजस्थान एक्स-सर्विसमैन कॉर्पोरेशन लि. (रेक्सको) के माध्यम से सेवाएँ ली जाएंगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में नवीन राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई थी।

नोट :

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2023 एवं ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल के समापन अवसर पर विभिन्न श्रेणियों में मिले पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

7 मई, 2023 को राजस्थान जवाहर कला केंद्र परिसर में आयोजित 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2023 व 3 दिवसीय ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल के समापन समारोह पर सहकार मेले में कारोबार एवं डिसप्ले की दृष्टि से विभिन्न समितियों को पुरस्कृत किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- सर्वश्रेष्ठ डिसप्ले के आधार पर राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में इफको, कृभको तथा शीर्ष सहकारी संस्थाओं में राजफैड, कॉनफैड, तिलम संघ, जयपुर डेयरी एवं अपैक्स बैंक को सम्मानित किया गया।
- राज्य विशेष के विशिष्ट उत्पादों एवं मसालों की बिक्री एवं प्रदर्शन हेतु मार्केफैड केरल, पंजाब, टैनफैड तमिलनाडु की सहकारी संस्थाओं को सम्मानित किया गया।
- ले-आउट के आधार पर ज़िला उपभोक्ता भंडारों की श्रेणी में उदयपुर, भरतपुर व भीलवाड़ा क्रमश: पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।
- सहकार मसाला मेले में सर्वाधिक बिक्री के लिये अन्य प्रदेशों में केरल स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन, शीर्ष संस्थाओं में प्रथम कॉनफैड व द्वितीय स्थान पर तिलम संघ रहा।
- क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में प्रथम मथानिया, दूसरा नागौर एवं तीसरा स्थान किशनगढ़ का रहा। इसी तरह से ज़िला उपभोक्ता भंडारों की श्रेणी में कोटा, उदयपुर व जोधपुर क्रमश: पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।
- इस मेले में जयपुरवासियों ने 2.10 करोड़ रुपए से अधिक के मसालों की खरीद की।
- गौरतलब है कि 28 अप्रैल, 2023 को राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2023 का शुभारंभ हुआ था।
- समापन समारोह में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार मेघराज सिंह रतनू ने श्रेष्ठ स्टॉलों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।
- आमजन को कॉनफैड के माध्यम से पहली बार जैविक कुकीज उपलब्ध कराने की शुरूआत की गई है।

नोट :

अजमेर के सिलोरी में होगी पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना

चर्चा में क्यों ?

7 मई, 2023 को राजस्थान के पुलिस कर्मचारियों की कार्यक्षमता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से अजमेर के सिलोरा (किशनगढ़) में प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना के लिये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्कूल के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

प्रमुख बिंदु

- यहाँ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, कंपनी कमांडर, प्रोग्रामर एवं वरिष्ठ सहायक के एक-एक पद, उप-निरीक्षक सीपी एवं प्लाटून कमांडर के 2-2 पद, हेड कांस्टेबल के 10 पद तथा कांस्टेबल के 18 (कुल 38) नवीन पदों का सृजन होगा।
- इसके अलावा व्याख्याता, प्लाटून कमांडर, बारबर, स्वीपर, कुक और हेड कांस्टेबल के कुल 15 पदों पर सेवानिवृत्त अथवा जॉब बेसिस के आधार पर सेवाएँ ली जाएगी।
- इसके साथ ही यहाँ विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये 4.34 करोड़ रुपए, उपकरणों के लिये 4.05 लाख रुपए और वाहनों के लिये 29.20 लाख रुपए व्यय करने की भी मंज़ूरी दी है।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की थी।

प्रत्येक ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति का होगा गठन

चर्चा में क्यों ?

8 मई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्थान के लिये राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन की कार्ययोजना के प्रारूप का अनुमोदन किया है।

प्रमुख बिंदु

- प्रत्येक समिति की अंशदान की 3 लाख रुपए राशि भी राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इस तरह राज्य में 351 ब्लॉक में बनने वाली ग्राम सहकारी सेवा समितियों के लिये कुल 10.53 करोड़ रुपए का वित्तीय भार राज्य सरकार वहन करेगी।
- प्रारूप के अनुसार, समिति के कार्यक्षेत्र में न्यूनतम एक ग्राम पंचायत होगी तथा न्यूनतम सदस्य संख्या 300 होगी। न्यूनतम हिस्सा राशि 3 लाख रुपए होगी।
- सामान्य क्षेत्रों में सदस्यों से न्यूनतम अमानत राशि 1 लाख रुपए तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में अमानत राशि 75 हज़ार रुपए होगी। किसी भी एक ग्राम पंचायत में दो ग्राम सहकारी सेवा समितियाँ नहीं होंगी।
- नई समितियों में फर्नीचर्स एवं अन्य संसाधनों के लिये 50 हज़ार रुपए प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों (पैक्स) से दिये जाएंगे।
- मुख्यमंत्री के इस निर्णय से सहकारिता क्षेत्र में महिलाओं का सक्रिय सहयोग बढ़ेगा। साथ ही, महिलाओं का सर्वांगीण उत्थान तथा सहकारिता आंदोलन को शक्ति, गति एवं दिशा भी मिल सकेगी।

दिल्ली में निवास कर रहे प्रवासी राजस्थानी लोगों को मिली महत्त्वपूर्ण योजनाओं की सौगात

चर्चा में क्यों ?

10 मई, 2023 को राजस्थान सरकार की मुख्य आवासीय आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह और आवासीय आयुक्त व राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने दिल्ली में निवास कर रहे प्रवासी राजस्थानी लोगों को राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिये दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस परिसर में 'मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना' और 'ई-मित्र' योजना का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- 'मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना' के तहत 300 दवाइयाँ नि:शुल्क रूप से लोगों को मिलेंगी।

नोट :

- इसके अलावा बीकानेर हाउस में खोले गए ई-मित्र केंद्र द्वारा करीब 500 विशिष्ट सेवाएँ दी जाएंगी, जिसमें मुख्य रूप से जनाधार, नामांकन, चिरंजीवी नामांकन, पेंशन सत्यापन, छात्रवृत्ति योजना, मोबाइल रिचार्ज, बस- रेल टिकट, जन्म- मृत्यु प्रमाण आदि शामिल हैं।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की शिक्षा और स्वास्थ्य की सकारात्मक सोच और प्राथमिकता का लाभ राज्य में रहने वाले लोगों के साथ-साथ राज्य के बाहर रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों को भी मिलना चाहिये। इसी संकल्प के साथ इन सुविधा केंद्रों का शुभारंभ किया गया है।
- बीकानेर हाउस परिसर में ई-मित्र और मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना केंद्रों के शुभारंभ के साथ-साथ पत्रकारों के बैठने के लिये एक पत्रकार कक्ष का उद्घाटन किया गया। इस कक्ष में पत्रकारों को बैठने की सुविधा के साथ-साथ कंप्यूटर और अन्य सुविधाएँ भी शुरू की गई हैं, ताकि मीडियाकर्मी अपने समाचार संबंधित दैनिक कार्य संपन्न कर सकें।

प्रदेश के सभी ज़िलों के राजकीय विद्यालयों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन

चर्चा में क्यों ?

11 मई, 2023 को राजस्थान के जनसंपर्क एवं सूचना विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश के स्कूली विद्यार्थियों में वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राजस्थान के सभी ज़िलों के राजकीय विद्यालयों में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- स्कूली विद्यार्थियों में वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करने की कड़ी में प्रदेश के जयपुर ज़िले में ब्लॉक स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन ग्रामीण विकास एवं स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मांचवा झोटवाड़ा में किया गया।
- इस प्रश्नोत्तरी में ज़िलों के सभी ब्लॉकों के राजकीय विद्यालयों के आठवीं से दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया गया।
- ब्लॉक स्तरीय प्रश्नोत्तरी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम ज़िला स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लेगी। इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम तीन विजेताओं को सम्मानित किया गया है।

प्रधानमंत्री ने नाथद्वारा में विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

10 मई, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के नाथद्वारा में 5500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि ये विकास परियोजनाएँ नाथद्वारा क्षेत्र में अवसंरचना और कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। रेलवे और सड़क परियोजनाएँ माल और सेवाओं की आवाजाही की सुविधा प्रदान करेंगी, जिनसे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा तथा क्षेत्र के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और राजस्थान की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी।
- प्रधानमंत्री ने राजसमंद और उदयपुर में दो-लेन वाली सड़क में उन्नयन से जुड़ी सड़क निर्माण परियोजनाओं की आधारशिला रखी। साथ ही प्रधानमंत्री ने लोगों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने के लिये उदयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी।
- उन्होंने आमान परिवर्तन परियोजना और राजसमंद में नाथद्वारा से नाथद्वारा शहर तक एक नई लाइन निर्माण का भी शिलान्यास किया।
- इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिनमें शामिल हैं- एनएच-48 के अंतर्गत उदयपुर से शामलाजी तक 114 किमी लंबी छह लेन वाली परियोजना; एनएच-25 के बार-बिलारा-जोधपुर खंड में दुपहिया आदि वाहनों के लिये सड़क को चौड़ा करने (पेव्ड शोल्डर) के साथ 110 किमी लंबी सड़क को 4 लेन का बनाने के लिये चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण परियोजना और एनएच 58ई में पेव्ड शोल्डर खंड के साथ 47 किमी लंबी सड़क का दो लेन वाली सड़क निर्माण परियोजना।

नोट :

- राष्ट्रीय राजमार्ग के उदयपुर से शामलाजी खंड को छह लेन करने से उदयपुर, डूंगरपुर और बाँसवाड़ा को फायदा होगा, वहीं एनएच-25 के बिलाड़ा-जोधपुर खंड से जोधपुर से सीमावर्ती इलाकों तक पहुँच आसान हो जाएगी। जयपुर-जोधपुर के बीच की यात्रा-अवधि में तीन घंटे की कमी आएगी तथा कुम्भलगढ़ और हल्दीघाटी जैसे विश्व विरासत स्थलों तक पहुँचना आसान हो जाएगा।
- श्री नाथद्वारा से नई रेलवे लाइन मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ेगी, जिससे संगमरमर, ग्रेनाइट और खनन उद्योग जैसे क्षेत्रों को मदद मिलेगी।

राजस्थान पुलिस अकादमी में बनेगी इंडोर शूटिंग रेंज

चर्चा में क्यों ?

10 मई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के पुलिसकर्मियों में फायरिंग क्षमता की वृद्धि के लिये जयपुर की राजस्थान पुलिस अकादमी में अत्याधुनिक इंडोर शूटिंग रेंज की स्थापना हेतु 14 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

- यह इंडोर शूटिंग रेंज स्पोर्ट्स से अलग एवं आधुनिक तकनीक की कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज (सीआईएसआर) होगी, जिसमें 50 मीटर की 6 लाइन होंगी।
- प्रशिक्षणार्थियों को इंडोर फायरिंग रेंज के बेहतर एवं अनुकूल वातावरण में अभ्यास करने के अवसर मिलेंगे।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।

बीकानेर में 1 नवीन संस्कृत विद्यालय और प्रदेश के 18 संस्कृत विद्यालय होंगे क्रमोन्नत

चर्चा में क्यों ?

14 मई, 2023 राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीकानेर ज़िले में 1 नवीन संस्कृत विद्यालय खोलेने और राज्य के विभिन्न ज़िलों के 18 संस्कृत विद्यालयों के क्रमोन्नयन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

प्रमुख बिंदु

- इसमें विभिन्न ज़िलों के 5 संस्कृत प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, 8 संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा 5 प्रवेशिका (माध्यमिक) संस्कृत विद्यालयों को वरिष्ठ उपाध्याय में क्रमोन्नत किया जाएगा।
- विदित है कि राज्य सरकार संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये नए विद्यालय की स्थापना और विभिन्न विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का प्रयास कर रही है।
- राज्य सरकार के इस निर्णय से संस्कृत शिक्षा के अधिक केंद्र खुलने के साथ ही विद्यार्थियों को नज़दीक ही पढ़ने के अवसर मिलेंगे।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में बजट-2023-24 में घोषणा की गई थी।

जोधपुर शहर का 565वाँ स्थापना दिवस

चर्चा में क्यों ?

12 मई, 2023 को राजस्थान के शौर्य, पराक्रम, अनुपम लोक संस्कृति और मनोहारी परंपराओं के साथ ही कई विलक्षण थातियों से भरे जोधपुर शहर का 565वाँ स्थापना दिवस विभिन्न मनोहारी एवं आकर्षक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया।

प्रमुख बिंदु

- जोधपुर स्थापना दिवस की शुरुआत रन फॉर जोधपुर के साथ हुई। इस दौरान विभिन्न लोक कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से स्थापना दिवस दौड़ को सांस्कृतिक रस-रंगों से भर दिया।
- इस अवसर पर अलग-अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने के लिये 2 अंतरराष्ट्रीय, 5 राष्ट्रीय, 11 राज्य स्तरीय और 1 लाइफटाइम अचीवमेंट सम्मान से हस्तियों को सम्मनित किया गया।

नोट :

- रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को राव सीहाजी सम्मान से नवाज़ा गया। वहीं मिस एनी विसेंट को महाराजा सरप्रताप सिंह सम्मान से नवाज़ा गया।
- समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिये रावल किशन सिंह को एवं श्रीरानी भटियाणी मंदिर संस्थान जसोल को राव जोधा जी सम्मान दिया गया।
- इस अवसर पर विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिये डॉक्टर रमेश रलिया को महाराजा हनुवंत सिंह सम्मान से सम्मानित किया गया, साथ ही सामान्य नागरिकों और रक्षा कर्मों के लिये असाधारण बहादुरी के क्षेत्र में मदन सिंह को मेजर दलपत सिंह सम्मान से नवाज़ा गया।
- पारंपरिक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिये अनूप शाह को कुँवर करणी सिंह जसोल सम्मान दिया गया।
- इसी कड़ी में राजस्थानी लोक संगीत और पारंपरिक कालबेलिया क्षेत्र में कालू नाथ कालबेलिया को पदमश्री कोमल कोठारी सम्मान ,लोक संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिये मरणोपरांत स्वर्गीय लीलादेवी सोमानी को महाराजा विजय सिंह सम्मान, धरोहर संरक्षण के क्षेत्र में ओंकार सिंह लखावत महाराजा मानसिंह सम्मान दिया गया।
- वहीं प्राकृतिक विरासत संरक्षण के क्षेत्र में डॉक्टर सरवन सिंह राठौड़ को महाराजा उम्मेदसिंह सम्मान, महिला सशक्तीकरण में ऐश्वर्या भाटी को राजदादीसा बदन कँवर भटियाणी सम्मान, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन को राजमाता कृष्ण कुमारी सम्मान ,रतन सिंह राजपुरोहित को गजसिंह द्वितीय सम्मान से नवाज़ा गया, राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी रवि विश्नोई को युवराज शिवराज सिंह सम्मान से सम्मानित किया गया।
- इसके अलावा पत्रकारिता के क्षेत्र में मारवाड़ मैगजीन को मुथा नैंसी सम्मान प्रदान किया गया।
- राजस्थानी भाषा साहित्य को बढ़ावा देने के लिये भँवरलाल सुथार को पदमश्री सीताराम लालस सम्मान, राजस्थानी भाषा काव्य साहित्य क्षेत्र में बीकानेर के हनुमंत सिंह कीकर को नारायण सिंह भाटी मालूंगा सम्मान तथा सुरेंद्र सिंह को मरणोपरांत राजाराम मेघवाल सम्मान से सम्मानित किया गया।
- आज़ादी से पहले कानून और न्याय क्षेत्र में योगदान के लिये वरिष्ठ अधिवक्ता लेखराज नेता को लाइफटाइम अचीवमेंट सम्मान दिया गया।
- उल्लेखनीय है कि राठौर वंश के प्रमुख राव जोधा ने वर्ष 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी। इस शहर का नाम उनके नाम पर ही रखा गया है। इसे पहले मारवाड़ के नाम से जाना जाता था।
- जोधपुर में ज्यादातर घर नीले रंग से रंगे हुए है. इसलिये इस शहर को 'ब्लू सिटी'या 'सन सिटी'भी कहा जाता है।
- जोधपुर शहर के स्थापना दिवस को लेकर हर साल भव्य कार्यक्रम का आयोजन के साथ सम्मान समारोह व अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं। इन कार्यक्रमों में अलग-अलग क्षेत्रों में विशेष व उल्लेखनीय काम करने वालों को सम्मानित किया जाता है। इस कार्यक्रम का आयोजन जोधपुर के महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों में से एक मेहरानगढ़ दुर्ग में किया जाता है।

नोट :

जयपुर व चित्तौड़गढ़ में खुलेंगे सैटेलाइट अस्पताल

चर्चा में क्यों ?

14 मई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के करबला क्षेत्र (हवामहल) और चित्तौड़गढ़ में सैटेलाइट चिकित्सालयों के खोले जाने की स्वीकृति दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निरोगी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की दिशा में इन सैटेलाइट चिकित्सालयों के खोले जाने की स्वीकृति दी है। इनके लिये 98 नवीन पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।
- इन दोनों चिकित्सालय में कनिष्ठ विशेषज्ञ के 5 पद, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी डेंटल, कनिष्ठ सहायक, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता, फार्मासिस्ट, डेंटल टैक्नीशियन, नेत्र सहायक के 1-1 पद, चिकित्सा अधिकारी व लैब टैक्निशियन संवर्ग के 4-4 पद, नर्स ग्रेड-प्रथम व रेडियोग्राफर संवर्ग के 2-2 पद, नर्स ग्रेड-द्वितीय के 15 पद, वार्ड बॉय के 6 पद एवं सफाई कर्मचारी के 4 पदों सहित कुल 98 पद सृजित होंगे।
- इन सैटेलाइट चिकित्सालयों के खुलने से आमजन को नज़दीक ही उपचार की बेहतर सुविधा मिल सकेगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।

नोट :

नदबई एवं लवाण के आयुर्वेद औषधालय को ब्लॉक आयुष चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

15 मई, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निरोगी राजस्थान की संकल्पना में आयुर्वेद की महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए भरतपुर ज़िले के नदबई एवं दौसा ज़िले के लवाण के आयुर्वेद औषधालय को ब्लॉक आयुष चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने इन चिकित्सालयों में 41 नवीन पदों के सृजन के लिये भी स्वीकृति दी है। नवीन सृजित पदों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारी विशेषज्ञ, यूनानी चिकित्साधिकारी, होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, वरिष्ठ आयुर्वेद नर्स, कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स, कनिष्ठ यूनानी नर्स, कनिष्ठ होम्योपैथिक नर्स, कनिष्ठ सहायक के पद शामिल हैं।
- इनके अलावा परिचारक, गार्ड, माली एवं पाचक की सेवाएँ संविदा से ली जाएंगी।
- मुख्यमंत्री ने अजमेर के केकड़ी में राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र के भवन निर्माण की भी मंजूरी दी है। इस कार्य में 8 करोड़ रुपए व्यय होंगे।
- मुख्यमंत्री के इस निर्णय से आयुष चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से स्वास्थ्य संवर्धन एवं रोगों के उपचार के लिये बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।

मुख्यमंत्री ने दी कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों को मिलने वाली पेंशन राशि में वृद्धि को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

15 मई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों को मिलने वाली पेंशन राशि में वृद्धि के वित्तीय प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

- कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों को अब प्रतिमाह 2500 रुपए पेंशन राशि मिलेगी। बढ़ी हुई पेंशन राशि 1 जून, 2023 (देय 01.06.2023) से मिलेगी।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रदेश में 16,810 कुष्ठ रोग मुक्त सामाजिक सुरक्षा पेंशनर हैं, जिन्हें वर्तमान में 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन राशि दी जा रही है, जिसे बढ़ाकर अब 2500 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।

225 ब्लॉक मुख्यालयों पर खुलेंगे होम्योपैथिक औषधालय

चर्चा में क्यों ?

16 मई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के 225 ब्लॉक मुख्यालयों पर होम्योपैथिक औषधालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने होम्योपैथिक औषधालयों के लिये 450 नवीन पदों के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की है।
- प्रस्ताव के अनुसार, 225 ब्लॉक मुख्यालयों पर खोले जाने वाले प्रत्येक होम्योपैथिक औषधालय में एक होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी एवं एक कनिष्ठ नर्स/कंपाउडर को नियुक्त किया जाएगा।

नोट :

- मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश का स्वास्थ्य ढाँचा सुदृढ़ होगा एवं आमजन को स्थानीय स्तर पर ही होम्योपैथिक उपचार उपलब्ध हो सकेगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में प्रत्येक ब्लॉक में होम्योपैथिक औषधालय खोले जाने की घोषणा की गई थी।

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को मिला 'द गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड्स'

चर्चा में क्यों ?

16 मई, 2023 को मलेशिया के पूलमैन क्वालालमपुर सिटी सेंटर होटल एंड रेजिडेंसेस में आयोजित कार्यक्रम में वर्ल्ड एचआरडी काउंसिल के निर्णायक मंडल ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के दो प्रोजेक्टों का चयन 'बेस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स'और 'बेस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर'के रूप में करते हुए बोर्ड को 'द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप'से सम्मानित किया है।

प्रमुख बिंदु

- आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा प्रशासनिक व्यस्तता के चलते स्वयं सम्मान समारोह में उपस्थित नहीं हो पाए अत: यह पुरस्कार मुख्य अभियंता प्रथम केसी मीणा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता संजय पूनिया और अमित अग्रवाल ने ग्रहण किया।
- वर्ल्ड एचआरडी कॉन्ग्रेस ने मानसरोवर स्थित सिटी पार्क को 'बेस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स' और प्रताप नगर स्थित कोचिंग हब को 'एक्सीलेंस इन इनोवेशन' की श्रेणी के लिये चयनित किया है।
- गौरतलब है कि राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त पवन अरोड़ा की अगुवाई में पिछले चार वर्षों में मंडल को कुल 17 अवार्ड मिल चुके हैं। इनमें मकान विक्रय में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, स्कॉच अवार्ड-2021, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा सम्मान, नेशनल हाउसिंग अवार्ड, आई.बी.सी. और 'स्टार ऑफ गवर्नेंस-गोल्ड अवार्ड' और नरेडको द्वारा दिये 'रियल एस्टेट कॉन्क्लेव'जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड शामिल हैं।

प्रदेश के प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों के अंशकालीन पुजारियों के मानदेय में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

16 मई, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों के अंशकालीन पुजारियों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने देवस्थान विभाग के अधीन आने वाले राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों के अंशकालीन पुजारियों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। इससे पुजारियों का मानदेय 3 हज़ार रुपए प्रतिमाह से बढ़कर 5 हज़ार रुपए प्रतिमाह हो जाएगा।
- मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पुजारियों को आर्थिक संबल मिलेगा।
- साथ ही, देवस्थान विभाग के अधीन 593 मंदिरों में पोशाक, रंग-रोगन, मरम्मत तथा उन्नयन संबंधी कार्यों के लिये 5.93 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृति दी है।
- उल्लेखनीय है कि आत्मनिर्भर मंदिरों के अंशकालीन पुजारियों का मानदेय 3 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 5 हज़ार रुपए पूर्व में ही किया जा चुका है।
- प्रस्ताव के अनुसार, 390 राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर तथा 203 राजकीय आत्मनिर्भर मंदिरों के लिये 5.93 करोड़ रुपए (प्रति मंदिर 1 लाख रुपए तक) की स्वीकृति दी गई है। उक्त स्वीकृति से मंदिरों में विभिन्न उन्नयन कार्य किये जाएंगे।
- राज्य सरकार द्वारा प्रदेशवासियों की आस्था को देखते हुए मंदिरों को सुदृढ़ करने के लिये पोशाक, रंग-रोगन एवं मरम्मत कार्य करवाए जा रहे हैं।
- मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में पुजारियों के मानदेय में वृद्धि तथा मंदिरों के मरम्मत, उन्नयन कार्या के संबंध में घोषणा की गई थी।

नोट :

प्रत्येक संभाग में स्थापित होगा सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्टस स्कूल

चर्चा में क्यों ?

17 मई, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में खेलों का वातावरण बनाने तथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य के प्रत्येक संभाग में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्टस स्कूल स्थापित करने के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

प्रमुख बिंदु

- प्रस्ताव के अनुसार, प्रदेश के बीकानेर, कोटा, अजमेर, उदयपुर एवं भरतपुर संभाग में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्टस स्कूल स्थापित किये जाएंगे, जिसके लिये 69.20 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
- मुख्यमंत्री के इस निर्णय से खिलाड़ियों को खेल के लिये उपयुक्त वातारण मिल सकेगा तथा संभाग स्तर पर आवासीय स्पोर्टस स्कूल होने से खिलाड़ियों को नज़दीक ही खेल सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में प्रत्येक संभाग में स्पोर्टस स्कूल खोलने की घोषणा की थी। प्रदेश के जयपुर एवं जोधपुर संभाग में आवासीय खेल स्कूल प्रारंभ करने की स्वीकृति पूर्व में ही दी जा चुकी है।

16 राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय माध्यमिक में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

17 मई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के उच्च प्राथमिक स्तर के 16 राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- प्रस्ताव के अनुसार, रामगढ़ अलवर, भणियाना साकड़ा जैसलमेर, उदयपुर, सीकर, बुरहान का तला बाड़मेर, कंचननेर भरतपुर, नंदेरा भरतपुर, मसूदा अजमेर, चूरू, सवाईमाधोपुर, नागौर, फतेहपुर सीकरी, तिजारा अलवर, घड़साना श्रीगंगानगर, कुछड़ी सम जैसलमेर तथा अभे का पार रामसर बाड़मेर स्थित आवासीय विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा।
- इनमें 9 बालक तथा 7 बालिका आवासीय विद्यालय हैं। इन विद्यालयों हेतु प्रधानाचार्य के 16, वरिष्ठ अध्यापक के 64, शारीरिक शिक्षक के 16 सहित कुल 96 पदों का सृजन किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से प्रदेश में उच्च एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये सुविधाओं का विस्तार होगा तथा विद्यार्थियों को आवासीय विद्यालयों की सुविधा मिल सकेगी। इससे विद्यार्थियों को घर के नज़दीक ही आगे की पढ़ाई जारी रखने के अवसर मिलेंगे।

मरुधरा का मान-स्वच्छता सम्मान-समारोह-2023

चर्चा में क्यों ?

17 मई, 2023 को राजस्थान पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने बताया कि जयपुर में स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के सभागार में ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन निदेशालय की ओर से 'मरुधरा का मान-स्वच्छता सम्मान समारोह-2023' आयोजित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग ने राजीविका के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वच्छता सखी के रूप में तैयार किया गया है। यह नवाचार आगे भी जारी रहेगा व स्वच्छता के अभियान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में सराहनीय कार्य करने वालों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
- 'Retrofit to Twin Pit' अभियान में सराहनीय कार्य करने पर समारोह में बीकानेर को प्रथम, सवाई माधोपुर को द्वितीय व जैसलमेर को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।

नोट :

- इसी क्रम में मॉडल विलेज श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य करने पर उदयपुर को प्रथम, श्रीगंगानगर को द्वितीय व सिरोही ज़िले को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।
- स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2023 में स्टार कैटेगरी की श्रेणी में सिरोही ज़िले को प्रथम, पाली को द्वितीय व उदयपुर को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।
- स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2023 में ओ.डी.एफ. प्लस श्रेणी में 01 अक्टूबर, 2022 से 30 अप्रैल, 2023 तक अधिक प्रगति प्राप्त करने वाले ज़िले में उदयपुर प्रथम, जयपुर द्वितीय व भरतपुर को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।
- 'मरुधरा का मान-स्वच्छता सम्मान समारोह-2023' में स्वच्छता से संबंधित उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को 'स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान-2023' से सम्मानित किया गया।
- गाँव को उत्कृष्ट श्रेणी में ओ.डी.एफ. प्लस बनाने में ग्राम पंचायत सुवांसा, पंचायत समिति तालेड़ा, ज़िला बूँदी की सरपंच प्रियंका गोस्वामी, ग्राम पंचायत खैरवाड़ा, पंचायत समिति खैरवाड़ा ज़िला उदयपुर की सरपंच लक्ष्मी देवी अहारी व प्लास्टिक कचरा प्रबंधन श्रेणी में ग्राम पंचायत कनौज, पंचायत समिति भदेसर, ज़िला चित्तौड़गढ़ की महिला सरपंच मंजू देवी जागेटिया का योगदान सराहनीय रहा।
- ग्रे-वाटर प्रबंधन में ग्राम पंचायत नाडोल, पंचायत समिति देसूरी, ज़िला पाली की सरपंच फुल कँवर व ग्राम पंचायत ताखोली, पंचायत समिति टोंक, ज़िला टोंक, जैविक अपघटनीय अपशिष्ट श्रेणी में ग्राम पंचायत लखा हाकम, पंचायत समिति रायसिंह नगर, ज़िला श्रीगंगानगर की ग्रामीण महिला तारावंती व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के घटकों की मॉनिटरिंग में सराहनीय कार्य करने पर सुमन चौधरी को 'स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान-2023' प्रदान किया गया।

'द साइबेरियन स्ट्रे'

चर्चा में क्यों ?

18 मई, 2023 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को राजभवन में कक्षा बारहवीं में अध्ययनरत छात्राओं आशी गालरिया और अस्मी ढाकर ने संयुक्त रूप से लिखी अपनी पुस्तक 'द साइबेरियन स्ट्रे'की प्रथम प्रति भेंट की।

प्रमुख बिंदु

- पुस्तक लेखक आशी गालरिया ने बताया कि उनकी यह पुस्तक जानवर और मनुष्य के प्रेम से जुड़ी मार्मिक कथा है। इसमें बच्चे एलन और उसके पालतू कुत्ते सफायर के रिश्तों के आलोक में कहानी के अनूठे सूत्र पिरोए गए हैं।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि लेखिका आशी इस समय जयश्री पेडीवाल ग्लोबल स्कूल की छात्रा है। उसने यह पुस्तक तब लिखने की पहल की थी जब वह आठवी की छात्रा थी। वह आरंभ से ही मेधावी रही है।

भारत में राज्यों की राजनीति

चर्चा में क्यों ?

18 मई, 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र को सुप्रसिद्ध लेखक प्रो. धर्मचंद जैन ने अपनी तीन भागों में प्रकाशित पुस्तक 'भारत में राज्यों की राजनीति'की प्रथम प्रति भेंट की।

प्रमुख बिंदु

- लेखक प्रो. धर्मचंद जैन ने बताया कि इस पुस्तक में राज्य राजनीति का प्रारंभ, चुनाव, एकदलीय प्रणाली, राज्यों में दल-बदल की राजनीति, साझा सरकारों का युग, केंद्र-राज्य संबंध, मध्यावधि चुनाव, जनादेश, समसामयिक राजनीतिक परिदृश्य के साथ ही राज्य-राजनीति का समग्र विश्लेषण किया गया है।
- पंचशील प्रकाशन, जयपुर द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में भारतीय संविधान और शासन से जुड़ी शोधपरक विश्लेषणात्मक सामग्री का विशेष रूप से समावेश किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि प्रो. धर्मचंद जैन की अब तक 47 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उन्हें प्रतिष्ठित 'महाप्रज्ञ प्रतिभा', 'अणुव्रत लेखक', 'विशिष्ट लेखक'आदि पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हो चुके हैं।

नोट :

अब हर ज़िले में दो लवकुश वाटिकाएँ

चर्चा में क्यों ?

20 मई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सभी ज़िलों में दो-दो लवकुश वाटिकाएँ विकसित करने हेतु 66 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इससे प्रदेश में इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री के निर्णय से इन वाटिकाओं में वन एवं वन्यजीवों से संबंधित मॉडल स्थापित होंगे, जिनसे बच्चों को पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण की शिक्षा मिल सकेगी। यहाँ इको ट्रेल पथों का निर्माण और प्रदर्शनी के लिये जगह बनेगी।
- इन वाटिकाओं का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित एवं जागरूक करना है।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में प्रत्येक ज़िले में एक-एक अतिरिक्त वाटिका विकसित करने की घोषणा की गई थी।

जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर शहर बनेंगे थ्री डी सिटी

चर्चा में क्यों ?

20 मई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के चार शहरों जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर में जीआईएस आधारित थ्री डी सिटी और राजधरा सैटेलाइट इमेजरी रिपोजिटरी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये 106.46 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार द्वारा शहरों के विकास की बेहतर प्लानिंग एवं प्रबंधन के लिये प्रदेश के जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर शहरों के जियोग्राफिक इनफार्मेशन सिस्टम (जीआईएस) आधारित थ्री डी सिटी मॉडल विकसित किये जाएंगे।
- इससे शहरों के मास्टर प्लान में लैंड यूज प्रस्तावित करना, नई सड़कों, फ्लाईओवर, नई कॉलोनियों के निर्माण व विस्तार, ड्रेनेज प्लान सहित विभिन्न कार्यों को धरातल पर उतारने, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढाँचे के विकास, परिवहन योजना, भूमि नियोजन, नगर नियोजन इत्यादि के प्रभावी आकलन, सिमुलेशन एवं योजना बनाने में आसानी होगी।

नोट :

- विकसित थ्री डी मॉडल का ऑगमेंटेड रियलिटी/वर्चुअल रियलिटी (AR/VR) द्वारा शहर का वर्चुअल टूर भी किया जा सकेगा।
- इसके अतिरिक्त राजधरा प्लेटफॉर्म पर राजस्थान की विभिन्न समयावधि की सैटेलाइट इमेजरी की रिपोजिटरी भी स्थापित की जाएगी। इससे विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं के अनुसार जैसे लेंड यूज, लेंड कवर, जलाशयों/जल स्रोतों एवं वन क्षेत्रों में परिवर्तन, फसल उपज अनुमान, शहरों के विकास एवं फैलाव इत्यादि के विश्लेषण में आसानी होगी।

राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022-23

चर्चा में क्यों ?

19 मई, 2023 को राजस्थान के कला साहित्य एवं संस्कृति मंत्री बी. डी. कल्ला ने राजस्थान साहित्य अकादमी का वार्षिक पुरस्कार-सम्मान समारोह 2022-23 में साहित्यकारों को संगीत, कला और साहित्य के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिये सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान साहित्य अकादमी का वार्षिक पुरस्कार-सम्मान समारोह हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (ओटीएस) के भगवत सिंह मेहता सभागार में आयोजित किया गया।
- समारोह में मीरा पुरस्कार, रांगेय राघव पुरस्कार, सुधींद्र पुरस्कार, देवीलाल सामर पुरस्कार, देवराज उपाध्याय पुरस्कार, कन्हैयालाल सहल पुरस्कार, शंभूदयाल सक्सेना पुरस्कार, सुमनेश जोशी पुरस्कार, परदेशी पुरस्कार, चंद्रदेव शर्मा पुरस्कार एवं सुधा गुप्ता पुरस्कार का वितरण किया गया।
- इस मौके पर विशिष्ट साहित्यकार सम्मान से प्रदेश के कई ख्यातनाम साहित्यकारों को भी सम्मानित किया गया।
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेषाधिकारी फारूक आफरीदी को भी साहित्य के क्षेत्र में उनके अहम योगदान के लिये विशिष्ट साहित्यकार सम्मान प्रदान किया गया।
- इन साहित्यकारों को मिला सम्मान-
  - 2022-23 के वार्षिक पुरस्कारों के तहत कथा एवं उपन्यास विधा में दिया जाने वाला रांगेय राघव पुरस्कार बाँसवाड़ा निवासी भरत चंद्र शर्मा को उनके उपन्यास 'पीर परबत-सी' के लिये दिया गया।
  - काव्य विधा के लिये दिया जाने वाला सुधींद्र पुरस्कार जयपुर के कवि मायामृग को उनकी कविता संग्रह 'मुझमें मीठा तू हैं'के लिये तथा एकांकी-नाटक के लिये दिया जाने वाला देवीलाल सामर पुरस्कार जयपुर निवासी अजय अनुरागी को नाट्य कृति 'रांग नंबर' के लिये दिया गया।
  - आलोचना क्षेत्र का प्रतिष्ठित देवराज उपाध्याय पुरस्कार भरतपुर मूल के राजाराम भादू को आलोचना-कृति 'कविता के आयाम'को तथा विविध विधाओं का कन्हैयालाल सहल पुरस्कार जयपुर के व्यंग्यकार यश गोयल को कृति 'नामुमकिन नेता'के लिये दिया गया।
  - बाल साहित्य के क्षेत्र में शंभूदयाल सक्सेना पुरस्कार कांकरोली की कुसुम अग्रवाल को उनकी पुस्तक 'हम सब एक हैं'के लिये दिया गया।
  - बहुप्रतिष्ठित मीरा पुरस्कार, रति सक्सेना को उनकी कृति 'हँसी एक प्रार्थना के लिये' के लिये प्रदान किया गया।
  - ये सभी पुरस्कार इकतीस हज़ार रुपए की राशि के हैं।
  - इक्कीस हज़ार रुपए की राशि वाला प्रथम प्रकाशित कृति सुमनेश जोशी पुरस्कार उदयपुर निवासी कथाकार तराना परवीन को कहानी संग्रह 'एक सौ आठ'के लिये दिया गया।

  नवोदित साहित्यकारों को भी अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया
- विद्यालय स्तरीय परदेशी पुरस्कार
  - कविता के लिये- महारानी गायत्री देवी कन्या विद्यालय, जयपुर की प्राचा शर्मा को 'सागर मोती एवं अन्य कविताएँ'के लिये,
  - कहानी के लिये- जवाहर नवोदय विद्यालय, पल्लू-हनुमानगढ़ की दिव्या सानप को कहानी 'खुशी के आँसू'के लिये,

नोट :

- निबंध के लिये- राउमावि अमरपुरा-उदयपुर की हर्षिता मीणा को निबंध 'नवाचारों का उद्भव'के लिये
- लघुकथा के लिये- राजकीय सार्दुल उमावि बीकानेर के अरमान नदीम की लघुकथा 'असली ताकत'के लिये दिया गया।

- महाविद्यालय स्तरीय चंद्रदेव शर्मा पुरस्कार
  - कविता के लिये- राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के हिमांशु भारद्वाज को 'स्पृहा और अन्य कविताएँ'के लिये,
  - कहानी के लिये- इक्कीस कॉलेज गोपल्याण-लूणकरणसर की निर्मला शर्मा को कहानी 'कोई चारा नहीं'के लिये,
  - एकांकी के लिये- माँ जालपा देवी राजकीय महाविद्यालय तारानगर की तनिष्का पड़िहार की एकांकी 'जागो प्यारे, जागो'के लिये,
  - निबंध के लिये- सोनादेवी सेठिया कन्या महाविद्यालय सुजानगढ़ की मैना कँवर को निबंध 'विगत और संभावनाएँ'के लिये दिया गया।
- सुधा गुप्ता महाविद्यालय स्तरीय कविता पुरस्कार महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय जोधपुर की सूरज कुमारी को 'प्रकृति की आवाज और अन्य कविताएँ'के लिये दिया गया।
- उल्लेखनीय है कि उक्त सभी पुरस्कारों के तहत पाँच हज़ार रुपए प्रति पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।

आहूस (डेनमार्क) एवं राजस्थान सरकार के बीच हुआ एमओयू

चर्चा में क्यों ?

19 मई, 2023 को राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी की उपस्थिति में सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में शहरी जल प्रबंधन के लिये आहूस, डेनमार्क एवं राजस्थान सरकार के बीच हुए एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रमुख बिंदु

- एमओयू पर राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव पीएचईडी एवं जल संसाधन डॉ. सुबोध अग्रवाल ने हस्ताक्षर किये जबकि आहूस (डेनमार्क) की ओर से डायरेक्टर प्लानिंग लुइसे पेपे के डिजिटल हस्ताक्षर हुए।
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी ने कहा कि डेनमार्क एवं राजस्थान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग की मार्च, 2021 में पहल की गई थी। राजस्थान एवं डेनमार्क के बीच आपसी सहयोग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
- शहरी पेयजल क्षेत्र में सेवाओं एवं गुणवत्ता में सुधार, वितरण तंत्र की दक्षता में वृद्धि से गैर-राजस्व जल (छीजत) में कमी, जल स्त्रोतों का समन्वित प्रबंधन तथा भूजल एक्विफर मैपिंग, अपशिष्ट जल प्रबंधन की योजना एवं पुनर्चक्रण, नदियों के कायाकल्प के लिये हरित समाधान आदि क्षेत्रों में राजस्थान एवं डेनमार्क मिलकर कार्य करेंगे।
- जलदाय मंत्री ने पानी के सदुपयोग एवं जल संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि डेनमार्क में पानी की छीजत शून्य है और वहाँ पानी का पूरा इस्तेमाल होता है। अलग-अलग तरीकों से पानी बचाने की उनकी तकनीक, पेयजल, अपशिष्ट जल प्रबंधन एवं पुनर्चक्रण, नदियों के कायाकल्प आदि में आपसी सहयोग से राजस्थान को इसका लाभ होगा।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय सहित विभिन्न स्तरों पर मंजूरी एवं प्रक्रियाएँ पूरी करने के बाद यह एमओयू हुआ है। इससे पेयजल प्रबंधन में स्मार्ट वाटर तकनीक, गैर राजस्व जल (छीजत) में कमी लाने, अपशिष्ट जल के ट्रीटमेंट एवं रिसाइकल के साथ ही नदियों के पुनरूद्धार में डेनमार्क का तकनीकी सहयोग मिलेगा।
- इस एमओयू के बाद जोधपुर, कोटा एवं जयपुर जैसे बड़े ज़िलों में कुशल जल प्रबंधन के क्षेत्र में आहूस एवं राजस्थान के बीच सहयोग बढ़ाया जाएगा।
- डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वान ने कहा कि डेनमार्क एवं भारत के बीच स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के साथ लंबे समय तक आपसी सहयोग की दिशा में सकारात्मक प्रयास किये जाएंगे।

नोट :

मुख्यमंत्री ने किया राज्य स्तरीय कला महोत्सव का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

22 मई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा भारतीय लोक कला मंडल के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय लोक कला मंडल परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय कला महोत्सव का परंपरागत नगाड़ा बजाकर शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने लोक कला मंडल परिसर में लगाई गई जनजाति विद्यार्थियों की कला प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा जनजाति विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई अलग-अलग शिल्पाकृतियों के साथ पेंटिंग्स के बारे में कलाकारों से जानकारी ली और उन्हें अपने कला कौशल को और अधिक निखारने का आह्वान किया।
- उल्लेखनीय है कि जनजाति छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के साथ-साथ परंपरा, संस्कृति तथा कला कौशल की रचनात्मकता में आगे लाने के उद्देश्य से कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
- इस दौरान न सिर्फ विविध रंगारंग गतिविधियाँ आयोजित होंगी बल्कि कला प्रोत्साहन हेतु जनजाति वर्ग के ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा विद्यार्थियों को चित्रकला, माण्डना, हस्तशिल्प कला का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
- विद्यार्थियों तथा कलाकारों द्वारा तैयार चित्रकला तथा हस्तशिल्प कला की प्रदर्शनी का आयोजन भी होगा। कला महोत्सव का समापन 24 मई को होगा।

नोट :

चिकित्सा शिक्षा विभाग और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू

चर्चा में क्यों ?

23 मई, 2023 को विज्ञान और मानविकी व स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान के चिकित्सा शिक्षा विभाग और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय (यूके) के बीच एमओयू हस्ताक्षरित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा टी.रविकांत और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय वाइस-डीन प्रोफेसर कीथ ब्रेनन की उपस्थिति में यह एमओयू साइन किया गया।
- टी. रविकांत ने बताया कि चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के निर्देशन में अनुसंधान साझेदारी विकसित करने के उद्देश्य से यह एमओयू साईन किया गया है। इससे अकादमिक गतिविधियों और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा तथा चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित होंगे।
- आपसी अनुभव साझा होने से मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ को वैश्विक पहचान मिलेगी तथा कैपेसिटी बिल्डिंग होगी।
- उन्होंने कहा कि राजस्थान पहला राज्य है, जहाँ प्रत्येक ज़िले में मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। इसके साथ ही अपने नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है।

वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. विनोद सोमानी हंस के कहानी संग्रह का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

23 मई, 2023 को अजमेर ज़िला कलक्टर डॉ. भारती दीक्षित ने हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा के नामचीन वयोवृद्ध साहित्यकार डॉ. विनोद सोमानी हंस के नव प्रकाशित कहानी-संग्रह 'चौराहे के तीन रास्ते'का विमोचन किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- डॉ. विनोद सोमानी हंस की यह 34वीं कृति है। यह कृति उनकी जीवन संगिनी विद्या सोमानी को श्रद्धांजलि-स्वरूप समर्पित है। विद्या सोमानी स्वयं जीवनपर्यंत लेखिका, प्रकाशक एवं समाजसेविका रहीं।
- डॉ. विनोद सोमानी हंस का लेखन आशा, विश्वास, दिशा बोधयुक्त व अध्यात्म से ओतप्रोत रहा है। पुस्तक 'चौराहे के तीन रास्ते'उनकी 23 कहानियों का संग्रह है। हर एक कहानी सामान्य से लेकर खास व्यक्ति के जीवन से जुड़ी घटनाओं, पात्रों को रेखांकित करती है।
- कहानियों में मनोविश्लेषणात्मक एवं वास्तविकता स्पष्ट उभरती है तथा पाठक को कहानी अपनी-सी लगती है। पुस्तक की समीक्षा राजस्थानी लेखिका साहित्य संस्थान, जयपुर की सचिव डॉ.सुषमा शर्मा ने की है।
- कहानीकार का लेखन, भाषा शैली, कथानक कुछ इस तरह है कि कहानी पढ़ते हुए पाठक को यथार्थ प्रतीत होता है। उसके मन मस्तिष्क में फिल्म की सी रील चलने लगती है। पुस्तक के शीर्षक 'चौराहे के तीन रास्ते' प्रश्नचिह्न छोड़ती है।
- डॉ. विनोद सोमानी हंस देश के अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से अलंकृत किये गए हैं। पुस्तक की प्रस्तुति आकर्षक है। पुस्तक सभी वर्गों के लिये पठनीय है।

मुख्यमंत्री ने किया 'जंगल सफारी'का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

22 मई, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर राज्य के उदयपुर ज़िले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य में 'जंगल सफारी'का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- जयसमंद अभयारण्य में 'जंगल सफारी'की शुरूआत से उदयपुर ज़िले में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही प्रदेश में एक प्रमुख इकोटूरिज्म साइट का विकास होगा तथा क्षेत्र में रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।
- विदित है कि जयसमंद अभयारण्य में प्रोजेक्ट लेपर्ड के तहत किये गए प्रयासों से वर्तमान में लेपर्ड की संख्या बढ़कर 19 हो चुकी है।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 1972 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने वन एवं वन्यजीव संरक्षण के महत्त्व को समझा और 'प्रोजेक्ट टाइगर' की नींव रखी। उसी का परिणाम रहा कि भारत में आज विश्व के 70 प्रतिशत बाघ हैं।
- ज्ञातव्य है कि राजस्थान में तीन टाइगर सफारी हैं। हाल ही में राज्य के चौथे टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में रामगढ़ विषधारी को विकसित किया गया है। कुंभलगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट हेतु समिति का गठन भी किया गया है।
- राज्य सरकार वन और वन्यजीव की सुरक्षा के लिये निरंतर प्रयासरत है। जैव विविधता को बनाए रखने के लिये वर्ष 2010 में ही राजस्थान जैविक विविधता नियम की अधिसूचना जारी की गई।
- प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 27 वन्यजीव अभयारण्य, 16 कंजर्वेशन रिजर्व और 4 टाइगर प्रोजेक्ट हैं। इन सभी के संरक्षण और संवर्धन के लिये अधिक संवेदनशीलता के साथ कार्य किये जा रहे हैं।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वन और पर्यावरण संरक्षण के लिये राज्य सरकार द्वारा कई ऐतिहासिक फैसले लिये गए हैं। इसी क्रम में प्रदेश में वन्यजीव, वन क्षेत्र एवं इकोटूरिज्म का निरंतर विकास किया जा रहा है।
- वर्तमान राज्य सरकार द्वारा ही इको-टूरिज्म पॉलिसी-2021 लागू की गई। साथ ही सरिस्का और मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बॉर्डर होमगार्ड लगाकर विशेष बाघ संरक्षण बल की स्थापना की गई है, जो कि एक अनूठी पहल है।
- इको-टूरिज्म के लिये प्रत्येक ज़िले में वन क्षेत्रों के निकट दो-दो इको-टूरिज्म लव-कुश वाटिका विकसित की जा रही है।
- चूरू के तालछापर अभयारण्य में वन्यजीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है तथा चंबल घड़ियाल अभयारण्य में पर्यटन की दृष्टि से बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।
- राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिये केंद्र सरकार, भारतीय वन्य जीव संस्थान और राज्य सरकार के बीच हुए करार से जैसलमेर में गोडावण का कृत्रिम प्रजनन केंद्र शुरू किया गया।

नोट :

- जयपुर के झालाना डूंगरी स्थित विश्व वानिकी उद्यान की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर में भी वानिकी उद्यान विकसित किये जा रहे हैं।

विदेशी धरा पर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को दो श्रेणियों में मिले 'द गोल्डन ग्लोब टाइगर अवाडर्स'

चर्चा में क्यों ?

23 मई, 2023 को राजस्थान हाउसिंग बोर्ड आयुक्त पवन अरोड़ा को मलेशिया से 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 'द गोल्डन ग्लोब टाइगर अवाडर्स'प्राप्त कर आए अधिकारियों ने ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र भेंट किये।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि 16 मई को मलेशिया में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को वर्ल्ड एचआरडी काउंसिल के निर्णायक मंडल ने 'बेस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स'और 'बेस्ट इनोवेटिव प्रोजक्ट ऑफ द ईयर'के लिये 'द गोल्डन ग्लोब अवाडर्स फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप' से सम्मानित किया था।
- प्रशासनिक व्यस्तता के चलते आवासन आयुक्त ने स्वयं नहीं जाकर पुरस्कार ग्रहण करने के लिये इंजीनियर्स को मलेशिया भेजा था।
- गौरतलब है कि आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा की अगुवाई में पिछले चार वर्षों में मंडल को कुल 17 अवार्ड मिल चुके हैं। इनमें मकान विक्रय में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्डस, स्कॉच अवार्ड-2021, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा सम्मान, नेशनल हाउसिंग अवार्ड, आई.बी.सी और 'स्टार ऑफ गवर्नेंस-गोल्ड अवार्ड'और नरेडको द्वारा दिये रियल एस्टेट कॉनक्लेव जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड शामिल हैं।

कृषि संकाय में अध्ययनरत छात्राओं की प्रोत्साहन राशि में तीन गुणा बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों ?

24 मई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि क्षेत्र में महिलाओं की सशक्तीकरण और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये 'कृषि अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन योजना'में नवाचार करते हुए बजट घोषणा 2023-24 में 'राजस्थान युवा कृषक कौशल व क्षमता संवर्द्धन मिशन'की शुरुआत की है, जिसके तहत छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में तीन गुणा तक बढ़ोतरी की गई है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बालिकाएँ कृषि के क्षेत्र में नवीनतम विधाओं का अध्ययन करें और औपचारिक शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त करें, जिससे न केवल परिवार की आय बढ़ेगी बल्कि वे राज्य और देश की समृद्धि में भी योगदान देंगी।
- इस मिशन के माध्यम से कृषि शिक्षा के प्रति छात्राओं का रुझान बढ़ाने एवं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार ने प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की है।
- कृषि आयुक्त कानाराम ने बताया कि मिशन के तहत राज्य में कृषि विषय को लेकर अध्ययन करने वाली 11वीं एवं 12वीं कक्षा की छात्राओं को प्रतिवर्ष 5 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 15 हज़ार की राशि प्रोत्साहन प्रदान की जाएगी।
- कृषि विज्ञान से स्नातक के विषयों जैसे कि उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी, खाद्य प्रसंस्करण के साथ ही स्नातकोत्तर (एम.एस.सी. कृषि) में अध्ययन करने वाली छात्राओं को 12 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 25 हज़ार रुपए प्रतिवर्ष दिये जाएंगे।
- इसी प्रकार कृषि विषय में पीएचडी करने वाली छात्राओं को 15 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 40 हज़ार रुपए प्रतिवर्ष (अधिकतम 3 वर्ष) प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
- इस मिशन के तहत गत 4 वर्षों में (17 दिसंबर, 2018 से मार्च 2023 तक) अध्ययनरत 84 हज़ार 583 छात्राओं को कुल 55 करोड़ 17 लाख 87 हज़ार रुपए का प्रोत्साहन दिया गया है, जिसमें वर्ष 2018-19 में 11 हज़ार 605 छात्राओं को 7 करोड़ 87 लाख 69 हज़ार रुपए का आर्थिक संबल दिया गया है।

नोट :

- इसी प्रकार वर्ष 2019-20 में 15 हज़ार 780 छात्राओं को 9 करोड़ 30 लाख 6 हज़ार रुपए का, वर्ष 2020-21 में 14647 छात्राओं को 10 करोड़ 75 लाख 23 हज़ार रुपए का तथा वर्ष 2021-22 में 20 हज़ार 867 छात्राओं को 12 करोड़ 84 लाख 56 हज़ार रुपए का प्रोत्साहन देकर लाभान्वित किया गया है।
- इसी प्रकार वर्ष 2022-23 में 21 हज़ार 684 छात्राओं को 14 करोड़ 40 लाख 33 हज़ार रुपए का आर्थिक संबल देकर कृषि संकाय लेने के लिये प्रोत्साहित किया गया है।
- बढ़ते हुए आँकड़े बताते हैं कि राज्य सरकार की यह मुहिम छात्राओं को कृषि संकाय चुनने के लिये लाभकारी सिद्ध हो रही हैं। इससे न केवल छात्राएँ कृषि के क्षेत्र में नवाचार कर रही हैं बल्कि देश में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं।
- मिशन में आवेदन करने के लिये छात्रा का राजस्थान का मूल निवासी होना तथा किसी भी राजकीय एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में कृषि संकाय में अध्ययनरत होना आवश्यक है।
- कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को राजस्थान युवा कृषक कौशल व क्षमता संवर्द्धन मिशन में आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज़ जैसे जन आधार कार्ड, गत वर्ष की अंकतालिका और मूल निवास प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड करना होता है।

मुख्यमंत्री ने किया अत्याधुनिक बस टर्मिनल का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

25 मई, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन को बेहतर आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाने हेतु राज्य की राजधानी जयपुर के सिंधी कैंप के केंद्रीय बस स्टैंड पर नवनिर्मित अत्याधुनिक बस टर्मिनल का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- नवनिर्मित टर्मिनल से आमजन को यात्रा में सुगमता होगी। सिंधी कैंप बस स्टैंड पर नवनिर्मित बस टर्मिनल में यात्रियों की सुविधा हेतु यात्री शेड, बुकिंग विंडो, कार्यालय उपयोग हेतु बेहतरीन कक्ष, आधुनिक शौचालय, वातानुकूलित यात्री प्रतीक्षालय, फूडकोर्ट एवं व्यवसायिक उपयोग हेतु परिसर होगा।
- इसके अतिरिक्त उक्त परिसर सीसीटीवी कैमरे, वाईफाई, पब्लिक अनाउन्समेंट सिस्टम, लिफ्ट, एस्केलेटर, फायर फाईटिंग सिस्टम एवं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा 15 किलो वॉट के सोलर प्लांट से युक्त होगा।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिला यात्रियों के लिये रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों के किराए में 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की। रियायती यात्रा का दायरा बढ़ने से महिलाएँ रोडवेज की साधारण बसों के साथ-साथ अब एक्सप्रेस, डीलक्स सहित सभी श्रेणी की बसों के किराए में 50 प्रतिशत छूट का लाभ ले सकेंगी।
- प्रदेश में सैटेलाइट एवं नए बस स्टैंड बनाए जा रहे हैं। जोधपुर में भी अत्याधुनिक बस स्टैंड तैयार किया जा रहा है। लक्खी मेलों में जाने वाले श्रद्धालुओं को भी किराए में छूट दी जा रही है। हरिद्वार में अपने दिवंगत जनों की अस्थी विसर्जन में जाने वाले लोगों के लिये नि:शुल्क यात्रा का प्रावधान किया गया है।
- प्रदेश में परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों को भी रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा उनके रहने और खाने का प्रबंध भी करवाया गया।
- राज्य सरकार द्वारा रोडवेज कर्मियों के लिये पुरानी पेंशन योजना एवं आरजीएचएस लागू की गई है।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वरिष्ठजनों एवं विशेष योग्यजनों को रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा के लिये आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड प्रदान किये।
- उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा बस अड्डों के उन्नयन के लिये 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 875 नई रोडवेज बसें खरीदी गई हैं तथा 500 नई बसें खरीदने का कार्य किया जा रहा है।

नोट :

राज्य के 5 संभागों में खोले जाएंगे आर-केट केंद्र

चर्चा में क्यों ?

25 मई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 5 संभागों में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (आर-केट) केंद्र खोलने के लिये 25.90 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (आर-केट) केंद्र प्रदेश के अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर एवं उदयपुर संभागों में खोले जाएंगे।
- नए आर-केट केंद्र कोटा के सर्वपल्ली राधाकृष्णन भवन (राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय), उदयपुर के विज्ञान भवन (मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय), भरतपुर के आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस विभाग (राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय), अजमेर के राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय तथा बीकानेर के स्कूल इनोवेशन हब (महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय) में खोले जाएंगे।
- मुख्यमंत्री के इस निर्णय से युवाओं को ब्लॉक चेन, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स एवं वर्चुअल रियलिटी आदि की एडवांस्ड तकनीकों के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही, इन केंद्रों में सर्टिफिकेट कोर्स और मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च कर सकेंगे।
- उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जयपुर में भी आर-केट स्थापित किया गया है। साथ ही, जोधपुर के राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कम इन्स्टीट्यूट के तत्वावधान में इसके अस्थायी कैंपस में भी आर-केट के कोर्स प्रारंभ किये जा चुके हैं।
- मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।

डूंगरपुर में राजकीय विधि महाविद्यालय का शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

28 मई, 2023 को राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम आयोग के अध्यक्ष डॉ. शंकर यादव ने प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र डूंगरपुर में राजकीय विधि महाविद्यालय का शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर राज्यमंत्री डॉ. शंकर यादव ने कहा कि एक साल में डूंगरपुर के गुमानपुरा ददोड़िया में विधि महाविद्यालय की इमारत बनकर तैयार हो जाएगी। इससे क्षेत्र के छात्रों को विधि क्षेत्र में करियर बनाने का अवसर मिलेगा, उन्हें विधि की पढ़ाई के लिये बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
- गुमानपुरा ददोड़िया में राजकीय विधि महाविद्यालय के निर्माण पर लगभग साढे+ चार करोड़ रुपए की लागत आएगी। लगभग 2500 वर्गमीटर में महाविद्यालय भवन बनेगा।
- महाविद्यालय के लिये 12 बीघा ज़मीन आवंटित की गई है। इसमें आठ कक्षा कक्ष, एक कॉन्फ्रेंस हॉल, छात्र-छात्राओं के लिये कॉमन रूम, ऑफिस ब्लॉक में प्रिसिंपल चेंबर के साथ ही अन्य आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। पहले सत्र में 60 विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा।
- राजकीय विधि महाविद्यालय खुलने से यहाँ के युवा जागरूक होंगे और कुरीतियों का खात्मा होगा। शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत मिलेगी। यह राजकीय विधि महाविद्यालय क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।
- विधायक गणेश घोगरा ने बताया कि पालवड़ा में कृषि महाविद्यालय का काम भी जल्द शुरू होगा। डूंगरपुर के बच्चों को पढ़ाई के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। डूंगरपुर में कृषि महाविद्यालय, तीरंदाजी अकादमी, विधि महाविद्यालय खोलने की घोषणा भी की गई है।

प्रदेश के 23 लाख किसानों को मिलेंगे प्रमुख फसलों के बीज मिनिकिट

चर्चा में क्यों ?

29 मई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 23 लाख लघु एवं सीमांत कृषकों को प्रमुख फसलों के प्रमाणित किस्मों के बीज मिनिकिट नि:शुल्क वितरित करने के लिये 128.57 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश के प्रत्येक किसान को बीज मिनिकिट में संकर मक्का के 5 किग्रा., सरसों के 2 किग्रा., मूंग व मोठ के 4-4 किग्रा. एवं तिल के 1 किग्रा. प्रमाणित किस्मों के बीज नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।
- जनजातीय कृषकों हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा तथा गैर जनजातीय कृषकों हेतु कृषि विभाग द्वारा बीज मिनिकिट की खरीद राजस्थान राज्य बीज निगम/राष्ट्रीय बीज निगम से की जाएगी।
- इन मिनिकिट का वितरण कृषि विभाग द्वारा राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि राज्य में बीज उत्पादन बढ़ाने तथा लघु और सीमांत किसानों को नि:शुल्क बीज उपलब्ध कराए जाने के लिये 'राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन' चलाया जा रहा है। इस मिशन के उत्कृष्ट परिणामों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
- विदित है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।

पोषण सूचकांकों में सुधार के लिये खरीदे जाएंगे 16.97 करोड़ रुपए के उपकरण

चर्चा में क्यों ?

29 मई, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न पोषण वृद्धि निगरानी उपकरण उपलब्ध करवाने के लिये 16.97 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री के इस निर्णय से आंगनबाड़ी केंद्रों में इंफेंटोमीटर, स्टेडियोमीटर, वज़न मापने की मशीन आदि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
- इससे शिशु एवं माताओं के वज़न, लंबाई सहित विभिन्न पोषण सूचकांकों की सटीक जानकारी मिल सकेगी एवं उन्हें वांछित पोषण दिया जा सकेगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।

राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश बने ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह

चर्चा में क्यों ?

30 मई, 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में जस्टिस ऑगस्टिन जार्ज मसीह को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया।

प्रमुख बिंदु

- पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने अंग्रेजी भाषा में शपथ ली।
- समारोह के प्रारंभ में राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु द्वारा जारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अधिसूचना एवं वारंट पढ़कर सुनाया।
- विदित है कि जस्टिस मसीह का जन्म 12 मार्च, 1963 को पंजाब के रोपड़ में हुआ था। उन्होंने सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल, कसौली (एचपी) में प्रारंभिक स्कूली शिक्षा ली और फिर सैफुद्दीन ताहिर हाई स्कूल, अलीगढ़ से स्कूली शिक्षा पूरी की।
- जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह सुप्रीम कोर्ट, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों की हाईकोर्ट में प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। वे सहायक महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता के पदों पर भी रहे।
- जस्टिस मसीह को 10 जुलाई, 2008 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप नियुक्ति मिली थी। 14 जनवरी, 2011 को उन्होंने स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी।

नोट :